प्रेरणा
छोटे फैसलों से ही बड़ी सफलता मिलती है।

सच कहने की ताकत | साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-6 • 11 JULY TO 17 JULY 2025 • VOLUME 50 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

साप्ताहिक मौसम

दिन	अधिकतम	न्यूनतम
शुक्रवार	34°	27°
शनिवार	34°	28°
रविवार	37°	27°
सोमवार	35°	28°
मंगलवार	33°	27°
बुधवार	33°	28°
वीरवार	34°	28°

*आंकड़े आईएमडी के अनुसार

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE CONSULTING | DESIGN | TRAINING
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY
CONFUSED ABOUT CAREER!
Unsure of what to do after 10th/12th/Graduation?
Whether to Study in India or Abroad?
What should I do after 10th-Science, Commerce or Arts?
Should I consider Computer or Mechanical Engineering?
What is better for me - MBA in Marketing or MBA in Finance?
Should I pursue Chartered Accountancy or Law after 12th?
Do I have the aptitude for Architecture and Designing?
Get Career Guidance from our Expert Career Counseling Team Free of Cost
E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9317776662, 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.
*T&C apply

केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित राज्यों को दी बड़ी राहत

1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की आर्थिक मदद को दी मंजूरी

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

केन्द्र सरकार ने असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड जैसे बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित राज्यों के लिए 1,066.80 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की मंजूरी दी यह धनराशि राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से केन्द्रीय हिस्से के रूप में दी गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस वर्ष एसडीआरएफ/एनडीआरएफ कोष से 19 राज्यों को 8 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है।मोदी सरकार हर परिस्थिति में राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है आर्थिक सहायता के अलावा, केन्द्र ने सभी बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित राज्यों को आवश्यक एनडीआरएफ टीमों, सेना की टीमों और वायु सेना सहायता सहित सभी लॉजिस्टिक सहायता भी प्रदान की है केन्द्र सरकार ने असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड जैसे बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित राज्यों के लिए 1,066.80 करोड़

रुपए की राशि जारी करने की मंजूरी दी है। छह बाढ़ प्रभावित राज्यों में से असम को 375.60 करोड़ रुपए, मणिपुर को 29.20 करोड़ रुपए, मेघालय को 30.40 करोड़ रुपए, मिजोरम को 22.80 करोड़ रुपए, केरल को 153.20 करोड़ रुपए और उत्तराखंड को 455.60 करोड़ रुपए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से केन्द्रीय हिस्से के रूप में दिए गए हैं। इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण ये राज्य प्रभावित हुए हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित राज्यों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार हर परिस्थिति में राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है। इस वर्ष, केन्द्र ने 14 राज्यों को एसडीआरएफ से 6,166.00 करोड़ रुपए और 12 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से 1,988.91 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, 05 राज्यों को राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 726.20 करोड़ रुपए और 02 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से 17.55 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं।

केन्द्र सरकार ने सभी बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने से प्रभावित राज्यों को आवश्यक एनडीआरएफ टीमों, सेना की टीमों और वायु सेना सहायता सहित सभी लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की है। मौजूदा मानसून के दौरान, 21 राज्यों/ केन्द्रशासित प्रदेशों में बचाव और राहत कार्यों के लिए 104 एनडीआरएफ टीमें तैनात की गई हैं।

पंजाब कैबिनेट ने दी 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' को मंजूरी

राज्य के लोगों को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का नकद रहित इलाज

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने देश की अपनी तरह की पहली योजना, मुख्य मंत्री सेहत योजना को मंजूरी दे दी। इसके तहत राज्य के निवासी 10 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार नकद रहित करवा सकेंगे। इस संबंध में निर्णय यहां मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनके आधिकारिक निवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। इसका खुलासा करते हुए मुख्य मंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब के लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान करने वाली यह योजना 2 अक्टूबर से शुरू होगी। पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य देखभाल के लिए व्यापक योजना के तहत लाया गया है। इस योजना का लाभ पंजाब की कुल तीन करोड़ आबादी को होगा और अब तक 550 से अधिक निजी अस्पतालों को इस योजना के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिसे आने वाले दिनों में एक हजार तक बढ़ाया जाएगा। पहले प्रत्येक परिवार केवल पांच लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता था, इस सीमा को अब बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। गुरु साहिबान की ओर से दिखाए गए 'सरबत के भले' के सिद्धांत पर चलते हुए पंजाब सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग की भलाई सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों सहित पंजाब का प्रत्येक नागरिक मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, इसके लिए आय की कोई सीमा नहीं है। पहले आय सीमा के मापदंड के कारण केवल चयनित परिवारों को ही इस योजना के तहत लाभ मिलता था, लेकिन अब सभी पंजाब निवासियों को इसका लाभ मिलेगा।

इस योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड, सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से जारी किए जाएँगे। इसके अलावा, लोग अपने वोटर कार्ड या आधार कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से भी स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

निवेशकों को बड़ी राहत

निवेशकों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने 4 जून, 2025 से पॉपुलर एक्ट या मेगा प्रोजेक्ट नीति के तहत विकसित किए गए प्रोजेक्टों से सीएलयू, ईडीसी, एलएफ और अन्य शुल्क वसूलने के लिए अधिसूचना लागू करने का निर्णय लिया है। पंजाब में ये शुल्क 4 जून, 2025 की व्यापक अधिसूचना के माध्यम से राज्य में स्थापित किए जाने वाले सभी नए रियल एस्टेट प्रोजेक्टों और 1 अप्रैल, 2025 से चल रहे प्रोजेक्टों की नई विस्तार योजनाओं पर लागू किए गए थे। अब मंत्रिमंडल ने इस अधिसूचना को 4 जून, 2025 से लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत यह निर्धारित किया गया है कि 4 जून, 2025 तक जमा किए गए प्रोजेक्टों से पुरानी नीति के अनुसार शुल्क लिया जाएगा और 4 जून, 2025 के बाद जमा की गईं अर्जियों से नई दरें लागू होंगी, जो 4 जून, 2025 से प्रभावी होंगी।

ईडी ने छांगुर बाबा पर कसा शिंकजा, संपत्ति की होगी जांच

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण रैकेट के कथित मास्टरमाइंड छांगुर बाबा पिछले हफ़्ते आतंकवाद निरोधी दस्ते द्वारा गिरफ़्तार किए जाने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ़्तार में आ गया है। ईडी ने छांगुर बाबा (असली नाम जलालुद्दीन) और उसके करीबी सहयोगियों के ख़िलाफ़ अपनी जाँच तेज़ कर दी है, ताकि कथित तौर पर संदिग्ध तरीकों से जुटाई गई 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति की जाँच की जा सके।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 जुलाई को जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की, जिस पर धर्मांतरण, विदेशी धन के दुरुपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा व सांप्रदायिक सद्भाव के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों का आरोप है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों की जाँच शुरू की है और जानकारी जुटाई है कि उसके पास 40

बैंक खातों में 106 करोड़ रुपये की धनराशि है, जो मुख्य रूप से मध्य पूर्व से प्राप्त हुई है।

प्रवर्तन निदेशालय ने आज, जाँच के दौरान, एटीएस लखनऊ के पुलिस अधीक्षक को एक पत्र भेजकर छांगुर बाबा के खिलाफ 16 नवंबर, 2024 को दर्ज की गई प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति, उनसे जुड़ी संस्थाओं का विवरण, उनके और उनके सहयोगियों से संबंधित बैंक खातों का विवरण और चल-अचल संपत्तियों का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। 10 जुलाई, 2025 को बलरामपुर के जिलाधिकारी को भी एक पत्र भेजकर छांगुर बाबा और उनके सहयोगियों की संपत्तियों का विवरण मांगा गया है। संबंधित बैंकों के एएमएल प्रकोष्ठों को प्राथमिकी में उल्लिखित बैंक खातों के बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए ईमेल भेजे गए हैं।

कनाडा में कपिल शर्मा के नए कैफे पर हुई गोलीबारी

नई दिल्ली. कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफ़े पर गोलीबारी की घटना हुई,

जब अज्ञात हमलावरों ने उस इमारत पर कई राउंड गोलियां चलाईं जहाँ कैफ़े स्थित है। बताया जा रहा है कि हमलावर एक कार में आए और तुरंत भाग गए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कपिल शर्मा के रेस्तरां, कैप्स कैफे को निशाना बनाया गया था या गोलीबारी का उद्देश्य हास्य कलाकार को धमकाना था। कपिल शर्मा ने हाल ही में सरे में कैफे खोला था। प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के कार्यकर्ता और भारत की राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) के रडार पर मोस्ट वांटेड आतंकवादी हरजीत सिंह लाडी ने गोलीबारी की ज़िम्मेदारी ली है।

गुजरात पुल हादसे में पहला एक्शन, चार इंजीनियरों को किया सस्पेंड

अहमदाबाद. बुधवार को वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाले मुजपुर-गंभीरा पुल के ढहने के बाद, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटना की उच्च-स्तरीय और विस्तृत जाँच के आदेश दिए हैं। प्राथमिक जाँच के आधार पर चार इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। कार्यकारी अभियंता एनएम नाइकवाला, उप-कार्यकारी अभियंता यूसी पटेल, उप-कार्यकारी अभियंता आरटी पटेल और सहायक अभियंता जेवी शाह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। गुजरात सरकार के सूचना विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाले मुजपुर-गंभीरा पुल पर हुए हादसे की विस्तृत और गहन उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों की एक टीम को दुर्घटनाग्रस्त मुजपुर-गंभीरा पुल पर अब तक की गई मरम्मत, निरीक्षण और गुणवत्ता जांच जैसे मुद्दों पर एक रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। विशेषज्ञों की टीम द्वारा दुर्घटनास्थल का दौरा करने के बाद, दुर्घटना के कारणों की

प्रारंभिक जांच के आधार पर, दुर्घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एनएम नाइकवाला (कार्यकारी अभियंता), यूसी पटेल (उप-कार्यकारी अभियंता), आरटी पटेल (उप-कार्यकारी अभियंता) और जेवी शाह (सहायक अभियंता) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने जनहित में राज्य के अन्य पुलों का भी तत्काल और गहन निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। वडोदरा जिले में महिसागर नदी पर बने पुल के ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बृहस्पतिवार को बढ़कर 16 हो गई जबकि तीन-चार लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। बुधवार सुबह पादरा कस्बे के निकट गंभीरा गांव के पास चार दशक पुराने पुल का एक हिस्सा ढह जाने से कई वाहन महिसागर नदी में गिर गए।

गुरुग्राम में टेनिस स्टार राधिका यादव की हत्या

गुरुग्राम. गुरुवार को 25 वर्षीय राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उसके ही पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना सुबह करीब 10:30 बजे गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित राधिका यादव के पारिवारिक आवास की पहली मंजिल पर हुई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार राधिका यादव के पिता ने उस पर लगातार तीन गोलियाँ चलाईं। राधिका को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। टेनिस खेलो डाट काम के अनुसार राधिका यादव की अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आईटीएफ) में युगल टेनिस खिलाड़ी के रूप में रैंकिंग 113 थी। वेबसाइट में बताया गया है कि राधिका यादव का जन्म 23 मार्च, 2000 को हुआ था और वह आईटीएफ युगल में शीर्ष 200 में शामिल थीं।

1500 महिला पंचों-सरपंचों को नांदेड़ साहिब के दर्शन को ले जाएगी : सीएम

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब सरकार ने गांवों के विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 1500 महिला सरपंचों और पंचों को पवित्र स्थल नांदेड़ साहिब के दर्शन के लिए भेजने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल नौवें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित है। उन्होंने कहा कि इन महिला सरपंचों-पंचों के आने-जाने और रहने-सहने का सारा खर्च पंजाब सरकार वहन करेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन महिला पंचायती प्रतिनिधियों के इस पवित्र स्थल पर जाने के लिए विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी और महाराष्ट्र में इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पंजाबी के दिल में नांदेड़ साहिब के प्रति बहुत श्रद्धा और महत्व है और कई लोगों के मन में जीवन में कम से कम एक बार दर्शन करने की इच्छा होती है। उन्होंने आगे कहा कि ये पंच-सरपंच महिला सशक्तिकरण की भावना की मिसाल हैं और सरकार इन्हें इस तीर्थ यात्रा के दर्शन के लिए ले जाकर उनके योगदान

का सम्मान करना चाहती है। भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि महिला सरपंच और पंच पंजाब और पंजाबियों के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए अरदास करेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस पहल को मजबूती से लागू करने के लिए आवश्यक रूपरेखा को अंतिम रूप दे रही है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने पंजाब के डैमों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के जवानों को तैनात करने की सहमति दी थी। मुख्य मंत्री ने घोषणा की कि वर्तमान सरकार इस निर्णय को वापस लेने के लिए शुक्रवार को पंजाब विधान सभा में प्रस्ताव पेश करेगी।

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना : नौकरियों, आर्थिक विकास और औपचारिकीकरण की एक उत्प्रेरक

जालंधर ब्रीज. अब जबकि दुनिया स्वचालन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत सरकार ने हाल ही में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को स्वीकृति दी है। यह एक बेहद ही सामयिक और सोचा-समझा कदम है। लगभग एक लाख करोड़ रुपये के परिव्यय वाली यह योजना भारत के उभरते रोजगार परिदृश्य, विशेषकर मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र, में एक साहसिक नीतिगत हस्तक्षेप है। अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को समर्थन देने के उद्देश्य से तैयार की गई यह ईएलआई योजना महज एक आर्थिक उपाय भर नहीं है - यह भारत की श्रमशक्ति के भविष्य में एक ऐसा रणनीतिक निवेश है, जो सीधे तौर पर सरकार के विकसित भारत@2047 के विजन का समर्थन करता है। ईएलआई देश में रोजगार सृजन का एक प्रमुख उत्प्रेरक बनने जा रहा है।

कई अन्य ऐसे देशों के उलट, जहां आबादी शीघ्र ही घटने लगेगी या घट चुकी है, भारत में अभी भी कार्यशील आयु वर्ग की एक ऐसी बड़ी आबादी है, जिसे रोजगार के अधिक अवसरों की जरूरत है। ईएलआई योजना का उद्देश्य नौकरी चाहने वालों और नौकरी देने वालों के बीच ही नहीं बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से अनौपचारिक कार्य एवं औपचारिक रोजगार के बीच की खाई को पाटना है।

रोजगार संबंधी तात्कालिक नतीजों से परे जाकर, इस बात पर गौर करना महत्वपूर्ण है कि ईएलआई योजना विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में भारत की प्रगति को मजबूत करती है। खासतौर पर, औपचारिक व दीर्घकालिक रोजगार को प्रोत्साहित करके एसडीजी 8 (सभ्य कार्य तथा आर्थिक विकास) और कम वेतन पाने वालों एवं पहली बार नौकरी चाहने वालों को लक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करके एसडीजी 1 (गरीबी उन्मूलन) तथा एसडीजी 10 (असमानताओं में कमी) के संदर्भ में।

सुश्री ज्योति विज
(महानिदेशक, फिक्की)

आधार-समर्थ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली (डीबीटी सिस्टम) के जरिए ईपीएफओ पंजीकरण एवं संवितरण के साथ इस योजना का जुड़ाव न केवल रोजगार सृजन बल्कि सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार भी सुनिश्चित करता है, जोकि एक न्यायसंगत और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत द्वारा किए गए ऐसे प्रयासों को मान्यता देते हुए, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने हाल ही में भारत की इस उपलब्धि को स्वीकार किया और आधिकारिक तौर पर अपने डैशबोर्ड पर इस तथ्य को प्रकाशित किया कि भारत की 64.3 प्रतिशत आबादी (2015 में 19 प्रतिशत की तुलना में), यानी 94 करोड़ से अधिक लोग अब कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के दायरे में हैं।

मैन्यूफैक्चरिंग पर जोर खासतौर पर स्वागत योग्य है। जैसे-जैसे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं नए सिरे से बदल रही हैं, भारत भी कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता वस्तुओं और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में तेजी से उभर रहा है। इन क्षेत्रों में दीर्घकालिक रोजगार सृजन का समर्थन करके, ईएलआई योजना पीएलआई योजनाओं, 'मेक इन इंडिया' तथा 'स्किल इंडिया' जैसी मौजूदा पहलों का पूरक बनने के साथ-साथ शहरी व अर्द्ध-शहरी, दोनों समूहों में औद्योगिक विकास को गति देगी।

अक्सर लागत संबंधी चिंताओं के कारण औपचारिक भर्ती को बढ़ाने में बाधाओं का सामना करने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को यह योजना महत्वपूर्ण राहत प्रदान करती है। नियोक्ता-पक्ष के प्रोत्साहन नई भर्ती की सीमांत लागत को कम करते हैं। इससे विस्तार, औपचारिकीकरण और श्रमशक्ति के उन्नयन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है।

वैश्विक स्तर पर, वेतन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं रोजगार को बढ़ावा देने में कारगर साबित हुई हैं। जर्मनी जैसे देश अप्रेंटिसशिप और दीर्घकालिक भर्ती के लिए नियोक्ता सब्सिडी प्रदान करते हैं। दक्षिण कोरिया युवा एवं वृद्ध श्रमिकों के नियोक्ताओं को लक्षित वेतन सहायता प्रदान करता है। सिंगापुर कौशल के उन्नयन (अपस्किलिंग) और रोजगार को कायम रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्य अवसर कर क्रेडिट (डब्ल्यूओटीसी) की व्यवस्था है, जो वंचित समूहों के व्यक्तियों की भर्ती करने वाले नियोक्ताओं को पुरस्कृत करता है। भारत की ईएलआई योजना हमारे विशाल अनौपचारिक श्रम बाजार, जनसांख्यिकीय लाभांश और डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार जैसी स्थानीय जरूरतों के अनुरूप वैश्विक स्तर की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का समावेश करती है।

ईएलआई योजना भारत की रोजगार नीति की परिपक्वता - अल्पकालिक राहत से हटकर दीर्घकालिक श्रम बाजार के विकास की दिशा में बदलाव - को दर्शाती है। ढलती उम्र वाली आबादी के साथ-साथ डिजिटल और हरित बदलावों जैसे व्यापक वैश्विक रुझानों की पृष्ठभूमि में, ऐसी कारगर नीतियां अधिक संख्या में लोगों को गुणवत्तापूर्ण नौकरियां सुलभ कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। फिक्की में, हम अपने सदस्यों से इस योजना का सदुपयोग करने हेतु आगे आने का आग्रह करते हैं। नियोक्ताओं- खासकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से जुड़े- को इसे वित्तीय लाभ से कहीं आगे बढ़कर देखना चाहिए। यह योजना परिचालन को बढ़ाने, युवा प्रतिभाओं का दोहन करने, वेतन भुगतान प्रणाली (पेरोल) का औपचारिकीकरण करने और स्थायी आर्थिक मूल्य सृजित करने का एक उपकरण है। उद्योग जगत के एक शीर्ष चैंबर के रूप में, फिक्की इस उद्देश्य का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नैनीताल से मात्र 50 किमी दूर है शिव मंदिर, पांडवों ने स्थापित की थी शिवलिंग

Trevelling

नैनीताल जा रहे टूरिस्ट के बीच इस मंदिर में जाने का क्रेज रहता है। लेकिन ये मंदिर केवल टूरिस्ट स्पॉट नही हैं। भगवान शिव के मुख्य मंदिरों में से एक यहां पर आने वाले भक्तों की मुरादें पूरी होती है। जानें कौन से जिले में बना...

• **जालंधर ब्रीज.** फीचर

हरे-भरे पहाड़ों की ऊंची चोटी पर भोले बाबा के कई मंदिर है। भगवान शिव के कुल 18 मुख्य मंदिरों में इस मंदिर की गिनती होती है। नैनीताल से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर बसा है मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर। जहां पर आने वाले भक्तों की मुराद जरूरी पूरी होती है। पहाड़ों की ऊंची चोटी पर बने इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग का इतिहास पांडवों के समय का है। जानें कहां बना है मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर।

पांडवों ने शिवलिंग किया था स्थापित

नैनीताल से 50 किमी की दूरी पर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर को लोग टूरिस्ट अट्रैक्शन मानते हैं। लेकिन इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग बेहद प्राचीन है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग लगभग 5350 साल पुराना है। जिसे पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान बनवाया था। यहां शिवलिंग के अलावा भगवान हनुमान, विष्णु और पार्वती माता की भी मूर्तियां स्थापित हैं। इस मंदिर में साधु-सन्तों का आश्रम है। इस मंदिर में साधु मुक्तेश्वर महाराज जी समाधि भी बनी है। जिनके शिष्य आज भी इस मंदिर से सटे एक कमरे में रहते हैं।

मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है

मूलरूप से ये मंदिर 2312 मीटर की ऊंचाई पर बने मुक्तेश्वर नाम की चोटी पर बना है। ये मंदिर नैनीताल जिले में आता है। नैनीताल से किसी भी प्राइवेट कैब या टैक्सी से इस मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। वहीं जो लोग नैनीताल जाते हैं वो यहां दर्शन करने अक्सर जाते हैं। तो अगली बार नैनीताल जा रहे हों तो इस मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन जरूर कर लें।

FASHION

स्लिम दिखना चाहती हैं तो कुर्ते पर बनवाएं वी नेक की यह डिजाइन

कुर्ते के गले पर वी नेक आपको स्लिम लुक देने में मदद करती है। लेकिन वी नेक में भी डिफरेंट वैरायटी हैं जिन्हें आप अपने सूट पर स्टिच करवा लें तो अट्रैक्टिव और स्लिम दोनों दिखेंगी।

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

वी नेकलाइन कुर्ता

मोटी हैं तो स्लिम दिखने के लिए अधिकतर वी नेकलाइन पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन एक जैसी वी नेकलाइन अगर बोरिंग दिखती है तो कुछ हटके डिजाइन को नेकलाइन पर स्टिच करवा सकती हैं। ये ना केवल आपको स्मार्ट दिखाने में मदद करेंगे बल्कि सारे सूट की डिजाइन को अलग लुक देंगे। तो अबकी बार जब कुर्ती स्टिच करवाने के लिए दें तो इन ब्यूटीफुल नेकलाइन को बनवाएं।

सिंपल वी नेकलाइन

सिंपल वी नेकलाइन जब भी स्टिच करवा रही हों तो ध्यान रहे कि कपड़े के बॉर्डर को नेकलाइन पर जरूर अटैच करवाएं। इससे क्लीन लुक मिलता है।

डीप वी नेक कॉलर

कॉलर तो सभी बनवाते हैं लेकिन कॉलर को पूरे बस्ट एरिया तक स्टिच करवाएं और गले को कंफर्टेबल लुक देने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लगवाएं।

डीप वी नेक

कुर्ते के नेक पर बॉर्डर की मदद से लांग वी नेकलाइन क्रिएट करें। फिर एक्स्ट्रा कपड़े को स्टिच कर राउंड शेप दें। इस तरह की नेकलाइन के बस्ट एरिया स्लिम दिखता है।

सेमी कॉलर वी नेक

बैक से सेमी कॉलर शेप देते हुए आगे की तरफ वी नेकलाइन बनवाएं। साथ ही इसे हाईलाइट करने के लिए अलग कलर के फैब्रिक की मदद से बॉर्डर बनवाएं। ये नेकलाइन इन दिनों काफी ट्रेंड में है।

यूनिक डिजाइन कॉलर

राउंड शेप नेकलाइन के साथ थोड़ा बढ़ाकर कपड़ा लगवाएं और इस तरह से बैक फोल्ड कर वी शेप नेकलाइन बना दें। ये यूनिक डिजाइन ग्रेसफुल दिखेगी।

राउंड शेप कॉलर विद वी नेक

राउंड शेप कॉलर को स्टिच करवाने के साथ थोड़ा सा वी शेप में बनवाएं। ये रेट्रो लुक आपकी कुर्ती पर जंचेगी और फेमिनिन लुक देगी।

बैक कॉलर विद वी नेक

कुर्ते के फ्रंट में वी नेक के साथ बैक टू फ्रंट कॉलर सिलवाएं। ये डिजाइन कुर्ते को फॉर्मल बनाती है और अट्रैक्टिव लगती है।

लैस की डिटेलिंग

कुर्ते पर वी नेकलाइन बनवाने के साथ ही रफल और लैस को लगवाएं। इससे कुर्ते का लुक चेंज हो जाएगा और स्टाइलिश नजर आने लगेगा।

मुंह में घुल जाएगा **पनीर** का हर टुकड़ा बस फ्राई करते हुए रखें ध्यान

कई महिलाओं की शिकायत होती है कि तेल में फ्राई करते वक्त कई बार पनीर टूट जाता है, सख्त हो जाता है या ज्यादा तेल सोख लेता है। इन सिंपल टिप्स को अपनाकर पनीर फ्राई करेंगी तो हर बार मिलेगा परफेक्ट टेस्ट।

• **जालंधर ब्रीज.** रेसिपी

बच्चे हों या बड़े, पनीर लगभग हर किसी की फेवरिट डिश है। घर में जब भी किसी का कुछ स्पेशल खाने का मन होता है, तो सबसे पहला जिक्र पनीर का ही आता है। मलाई पनीर, शाही पनीर, मटर पनीर, पनीर फ्राई और भी ढेर सारी रेसिपीज हैं, जो पनीर से बनती हैं। इन सबमें एक बात कॉमन है कि पनीर की ज्यादातर डिशेज बनाने से पहले उसे तेल में तलना होता है। कई महिलाओं की शिकायत होती है कि तेल में फ्राई करते वक्त कई बार पनीर टूट जाता है, सख्त हो जाता है या ज्यादा तेल सोख लेता है। कभी कभी हद से ज्यादा नर्म भी हो जाता है, जो खाने में एकदम टेस्टी नहीं लगता। आज हम आपके लिए इन्हीं प्रॉब्लम्स का हल ले कर आए हैं। इन सिंपल टिप्स को अपनाकर पनीर फ्राई करेंगी तो हर बार मिलेगा परफेक्ट टेस्ट।

पनीर तलने का सही तरीका

- पनीर तलते समय तेल की मात्रा का भी ध्यान रखें। बहुत ज्यादा तेल डालने से पनीर उसे सोख लेगा और चिकना हो जाएगा। वहीं, अगर आप पैन में बहुत कम तेल डालती हैं तो ऐसे में पनीर पैन से चिपक जाता है और टूट सकता है। पैन में एक-दो बड़े चम्मच से ज्यादा तेल न डालें।
- पनीर तलते समय पहले पैन को ठीक तरह से गर्म करना बेहद जरूरी है। अगर पैन पर्याप्त गर्म नहीं है, तो ऐसे में पनीर नमी छोड़ सकता है और सतह पर चिपक जाता है। वहीं, अगर पैन बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उसकी बाहरी परत जल जाती है।
- पनीर को तलते वक्त अकसर लोग पैन में पनीर के ढेर सारे टुकड़े डाल देते हैं। ऐसा करने से तेल का तापमान कम हो जाता है और पनीर क्रिस्पी होने के बजाय नरम हो जाते हैं। क्रिस्पी पनीर तैयार करने के लिए हमेशा कम-कम मात्रा में पनीर को तलें ताकि हर टुकड़े को पर्याप्त जगह मिल सके।
- पनीर को तलते समय उसे जल्दी-जल्दी और बार-बार पलटने से बचें। अगर पनीर को लगातार पलटा जाता है तो ऐसे उसमें सही से भूरापन नहीं आता। वहीं, बहुत ज्यादा पलटने से क्रस्ट नहीं बनता और पनीर टूट सकता है।
- अकसर पनीर को फ्राई करने के बाद उसका टेक्सचर बिगड़ जाता है। ऐसा न हो इसके लिए पनीर को फ्राई करने के साथ दूसरे गैस पर पानी उबालें और उसमें एक चम्मच नमक डालें। तले हुए पनीर को इस गर्म पानी में पांच मिनट के लिए डाल दें और फिर प्लेट में निकाल लें।

मां-बाप की बदनामी का कारण बनते हैं ऐसी आदतों वाले बच्चे

जालंधर ब्रीज (फीचर) . बचपन इंसान की जिंदगी की नींव होती है। एक बच्चा अपने बचपन में किस तरह का बिहेवियर सीख या कर रहा है, उसका असर आने वाले फ्यूचर में उसकी पूरी पर्सनालिटी पर पड़ता है। ऐसे में समय रहते ऐसी बिहेवियर की पहचान करना जरूरी है और उसे रोकना भी।

झूठ बोलने की आदत : अगर बच्चा बार-बार झूठ बोलने लगे, तो ये बहुत ही खराब आदत है। यूं तो शुरू में ये आदत खेल-खेल में या किसी डांट से बचने के लिए होती है, लेकिन अगर बच्चे को समय रहते समझाया ना जाए तो बच्चा धीरे-धीरे इसे सही समझने लगता है।

बड़ों से बदतमीजी करना : कई बच्चे अपने से बड़ों से बात करते समय शिष्टाचार का ध्यान नहीं रखते। वे चिल्लाकर बोलते हैं या उल्टा जवाब देते हैं। बच्चे की ये आदत बहुत ही खराब होती है। ऐसे में ये जरूरी है कि बच्चे को बड़े और छोटे दोनों का लिहाज करना सिखाया जाए।

चुगली करने की आदत : कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो बातें इधर-उधर करना सीख जाते हैं। जब बच्चे बातें इधर-उधर करने लगते हैं, तो लोग सीधा उनकी पेरेंटिंग पर ही सवाल उठाते है। ऐसे बच्चे बाद में बड़े होकर भी इसी तरह की हरकते करते हैं।

दूसरों की नकल करना या मजाक उड़ाना : बच्चे अक्सर किसी की चाल, बोलने के ढंग की नकल करते हैं। ये बदतमीजी और अनकल्चर्ड बिहेवियर की कैटेगरी में आ जाता है। बच्चों की इस हरकत की वजह से पेरेंट्स को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इसलिए बच्चे अगर इस तरह की हरकत करें तो उन्हें प्यार से समझाएं कि किसी का मजाक उड़ाना गलत है।

लालच करना : अगर कोई बच्चा हर चीज को लेकर लालच करने लगता है, सब चीज अपने ही पास रखना चाहता हो और दूसरों से बांटना नहीं चाहता तो ये आदत भी आगे चलकर उसकी पर्सनैलिटी को खराब करती है। ऐसे बच्चे धीरे-धीरे सेल्फिश होने लगते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इन्हें दूसरों की परवाह नहीं होती है। इसलिए बचपन से ही बच्चे को शेयरिंग और केयरिंग का पाठ पढ़ाना चाहिए।

छोटे-छोटे रस से भरे, ना छिलका ना बीज, खाने से मिलते हैं इतने सारे फायदे

• **जालंधर ब्रीज.** हेल्थ केयर

health alert know why do we sweat after taking bath

जामुन के कलर के और अंगूर के जैसे गुच्छों में लगे हुए दिखते हैं शहतूत, लेकिन आकार बिल्कुल छोटा। इन फलों में ना छिलका होता है और ना ही बीज। रसीले शहतूत, जिसे मलबेरी भी कहते हैं, खाने से कई सारे फायदे मिलते हैं।

भारत में पूरी दुनिया के फलों में से लगभग 25 प्रतिशत वैरायटी पाई जाती है। हर रंग और हर किस्म के फल पूरे इंडिया में मिल जाएंगे। सबसे खास बात कि इन फलों में ढेर सारे न्यूट्रिशन होंगे। जिन्हें खाने से ना केवल आपको स्वाद मिलेगा बल्कि सेहत भी दुरुस्त रहेगी। खट्टे-मीठे,उमामी और लगभग हर स्वाद के फल जिनमे से एक है शहतूत। जिसकी बात जरा कम ही होती है। शहतूत लगभग हर हिस्से में मिलता है। उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर और साउथ के राज्यों में भी आसानी से मिल जाता है। शहतूत की खेती आमतौर पर रेशम पैदा करने के लिए की जाती है। लेकिन इसके फल भी बहुत गुणकारी होते हैं। शहतूत को इंग्लिश में मलबेरी कहते हैं। और, इस फल की खासियत है कि इसमे ना छिलका होता है और ना ही बीज। ढेर सारे छोटे-छोटे रस से फरे दाने जो मिलकर अंगूर जैसा रूप लेते हैं लेकिन आकार में बिल्कुल छोटे। इन्हें इसी रह से खाया जाता है। शहतूत खाने के कई सारे फायदे है। जिन्हें जरूर जानना चाहिए।

शहतूत में होते हैं ढेर सारे न्यूट्रिशन - शहतूत में विटामिन सी और के पाया जाता है। साथ ही आयरन, कैल्शियम और पोटैशियम की अच्छी मात्रा होती है। इसके साथ ही ये फल डायटरी फाइबर और फ्लेवेनाइड्स से भरपूर होते हैं।

विटामिन सी रिच है तो मिलेंगे ये फायदे - विटामिन सी रिच होने की वजह से शहतूत खाने से ना केवल इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है बल्कि इंफेक्शन और बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है।

आयरन की कमी करेगा दूर - शहतूत में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए जिन लोगों के शरीर में आयरन की कमी होती है। उन्हें इस फल या फलों के जूस को जरूर पीना चाहिए।

कैंसर का रिस्क कम करता है - ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में सेल्स और टिश्यू के डैमेज को बढ़ा देता है। जिससे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। शहतूत का जूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। जिससे कैंसर का रिस्क कम होता है।

ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करेगा - शहतूत में ऐसा कंपाउंड डीएनजे पाया जाता है जो ऐसे एंजाइम को बढ़ाता है जिसकी मदद से गट में कार्ब्स टूटते हैं। जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढता नहीं है और आसानी से कंट्रोल में रह सकता है।

कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है - स्टडी में पता चला है कि शहतूत के एक्सट्रेक्ट में ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो एक्सेस फैट को घटाने के साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। ये गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस करता है।

प्रगति का आधार - नवाचार, समावेश और पहचान का एक दशक

जालंधर ब्रीज . हम वस्त्रों की बात अक्सर व्यापार की भाषा जैसे निर्यात, घाटा और अधिशेष के रूप में करते हैं। लेकिन यह संकीर्ण दृष्टिकोण उस पैमाने से चूक जाता है जो वास्तव में काम कर रहा है। भारत के वस्त्र क्षेत्र की ताकत केवल उसके विदेशी शिपमेंट में ही नहीं है। यह कहीं ज़्यादा स्थायी चीजों में निहित है। बढ़ती जनसंख्या, एक ऐसा घरेलू ईंजन है जो धीमे होने से इनकार करता है और यह विरासत और नवाचार दोनों के उभरते हुए स्वभाव को दर्शाता है। यह 143 करोड़ भारतीयों द्वारा संचालित है जो अपने पहनावे, अपने घरों और अपनी परंपराओं में आराम, पहचान और आकांक्षा बनाए रखते हैं।

गिरिराज सिंह
(केंद्रीय वस्त्र मंत्री, भारत सरकार)

इस क्रांति का प्रसारण नहीं किया गया। इसे बुना गया। जहां दुनिया डिजिटल सफलताओं और बुनियादी ढांचे में तेजी को ट्रैक कर रही थी, वहीं भारत के करघों पर कुछ शांत और गहरा सामने आ रहा था। जिस को कभी विरासत उद्योग के रूप में खारिज कर दिया गया था आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उसे लचीलेपन, नवाचार और गौरव की शक्ति में बदल दिया गया है। भागलपुर के चमकते रेशम से लेकर पानीपत के पुनर्चक्रित धागों तक, परिवर्तन धीर, स्थिर और स्थायी है।

यह पुनरुत्थान नहीं है। यह पुनर्जागरण है। 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के लिए नींव को कंक्रीट और इस्पात से आगे ले जाना होगा। उन्हें समुदायों, आजीविका और सांस्कृतिक निरंतरता पर आधारित होना चाहिए। वस्त्र क्षेत्र की तुलना में इस दृष्टिकोण को कहीं और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस नहीं किया गया है। 4.6 करोड़ लोगों के साथ दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता होने के नाते, यह एक उद्योग से अधिक है। यह कौशल, पहचान और अवसरों का जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है। कभी पिछड़ा समझे जाने वाला यह उद्योग धीरे-धीरे आधुनिक आर्थिक इंजन में बदल गया है। अब पारंपरिक बुनाई वैश्विक बाजारों में प्रवेश कर रही है, जबकि तकनीकी वस्त्र एयरोस्पेस और कृषि में अपनी पैठ बना रहे हैं। और जमीनी स्तर पर, प्रत्येक करघा और चरखा गरिमा, नवीनीकरण और शांत शक्ति की गहरी कहानी दर्शाता है।

विकास का एक दशक: आंकड़े जो बताते हैं एक कहानी : जब हमारी सरकार ने 2014 में कार्यभार ग्रहण किया था, तो भारत का वस्त्र क्षेत्र विरासत में निहित एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में दिशाहीन था। कभी ठहराव से चिह्नित, वस्त्र क्षेत्र के पैमाने और संरचना को समर्थ के तहत लक्षित कौशल, कपास उत्पादकता मिशन, पीएलआई योजना और पीएम मित्र पार्क के जरिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के मिशन के रूप में नए युग के निवेश के माध्यम से फिर से बुना गया है।

भारत का कायाकल्प : मोदी नेतृत्व प्रभाव

मानदंड	2014	2025
कपास एमएसपी मीडियम स्टेपल	3700 रुपए	7710 रुपए
भारतीय कपास निगम की खरीद	22.86 लाख गांठ	100 लाख गांठ
रेशम क्षेत्र में रोज़गार	78 लाख	98 लाख
रेशम उत्पादन	26,000 मीट्रिक टन	41,115 मीट्रिक टन
जूट विविधीकृत उत्पादों का कुल निर्यात	1,470 करोड़ रुपए	3,000 करोड़ रुपए से अधिक
हस्तशिल्प निर्यात	29,000 करोड़ रुपए	49,000 करोड़ रुपए
तकनीकी वस्त्र निर्यात	नगण्य	3 बिलियन डॉलर

भारत के वस्त्र क्षेत्र में रोजगार 2014 में 3 करोड़ से तेजी से बढ़कर आज 4.6 करोड़ हो गया है, जिससे कुशल और अकुशल श्रम को अवशोषित करने के अवसर और क्षमता दोनों में मजबूत विस्तार हुआ है। घरेलू मांग में वृद्धि और उत्पादन की तेजी से प्रेरित होकर बाजार का आकार 112 बिलियन डॉलर से बढ़कर 176 बिलियन डॉलर हो गया है। परिधान निर्यात लंबे समय से इस क्षेत्र की आधारशिला है, वह 14 बिलियन डॉलर से बढ़कर 18 बिलियन डॉलर हो गया है, जो मूल्यवर्धित उत्पादन में लगातार लाभ को दर्शाता है। काफी समय से लंबित भारत-यूके एफटीए को आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अंतिम रूप दिया गया है। यह भारत के श्रम-प्रधान वस्त्र क्षेत्र के लिए विनिर्माण और निर्यात के एक वैश्विक केंद्र के रूप में राष्ट्र के उत्थान के लिए द्वार खोलकर निर्णायक बढ़त का वादा करता है।

लेकिन ये मात्र आंकड़े नहीं हैं बल्कि उससे कहीं बढ़कर हैं। वे एक रणनीतिक रीसेट का संकेत देते हैं। अस्थायी उपायों से दीर्घकालिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए, हमारी सरकार ने मानव निर्मित रेशों, नए युग के रेशों और तकनीकी वस्त्रों को अपनाने के लिए उद्योग के दायरे को उसके कॉटन कोर से आगे बढ़ाया है। जिन क्षेत्रों को कभी अनदेखा किया गया था, वे अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हैं। यह विजन अब केवल घरेलू धागों तक सीमित नहीं है। यह भारत के वस्त्रों को लचीलेपन, कौशल और स्थिरता के साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने पर आधारित है। यह परिवर्तन संयोग से नहीं हुआ है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रित शासन, साहसिक सुधारों और अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम है।

कपास के खेतों से कार्बन फाइबर तक विस्तार : भारत की वस्त्र गाथा आज पारंपरिक धागों से कहीं आगे है, जो कपास के खेतों से लेकर कार्बन फाइबर तक, हथकरघा से लेकर उच्च निष्पादन वाले तकनीकी वस्त्रों तक फैली हुई है। जमीनी स्तर पर, सरकार ने प्राकृतिक रेशों को अभूतपूर्व सहायता प्रदान की है। कपास उत्पादकता के लिए नए मिशन के साथ, भारत का लक्ष्य 2030 तक कपास उत्पादन को 5.70 से 7.70 एमएमटी और उत्पादकता को 439 से 612 किलोग्राम/हेक्टेयर तक बढ़ाना है। वर्तमान में, कपास वैश्विक कपास निर्यात बाजार का 3.16 प्रतिशत और कस्तूरी कपास का सिर्फ़ 1 प्रतिशत हिस्सा है। कपास उत्पादकता मिशन के तहत, हमारा लक्ष्य 2030 तक इसे प्रीमियम वैश्विक कपास निर्यात का 10 प्रतिशत बनाना है। पिछले 11 वर्षों में भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद में 338 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि मध्यम और लंबे रेशे वाले कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दोगुने से अधिक हो गए हैं, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। रेशम उत्पादन में 58 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। यहां तक कि जूट, जो कभी एक घटता हुआ खंड था, उसमें भी नई गति देखी गई है।

ऑपरेशन सिंदूर में वीरता और स्वदेशी उपकरणों की ताकत ने वैश्विक मांग को बढ़ावा दिया : रक्षा मंत्री

जालंधर ब्रीज . रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 07 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) के नियंत्रक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सशस्त्र बलों की परिचालन तत्परता और वित्तीय दक्षता को दुरूस्त करने में विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में प्रदर्शित वीरता और घरेलू उपकरणों की क्षमता के प्रदर्शन ने स्वदेशी उत्पादों की वैश्विक मांग को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया हमारे रक्षा क्षेत्र को नए सम्मान के साथ देख रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रक्रियाओं में एक भी देरी या त्रुटि सीधे परिचालन तैयारियों को प्रभावित कर सकती है। सिंह ने रक्षा में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के साथ तालमेल बिठाते हुए डीएडी को 'नियंत्रक' से 'सुविधाकर्ता' के रूप में विकसित होने का भी आह्वान किया।

राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में चल रहे परिवर्तन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को दिया, जिनके मार्गदर्शन में देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा है और रक्षा नियोजन, वित्त तथा नवाचार में संरचनात्मक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा, "हम जो उपकरण पहले आयात करते थे, उनमें से अधिकांश अब भारत में ही बनाए जा रहे हैं। हमारे सुधार उच्चतम स्तर पर दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता की स्पष्टता के कारण सफल हो रहे हैं।"

रक्षा मंत्री ने स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, 2024 में बढ़ते वैश्विक सैन्य व्यय के 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का उल्लेख किया और कहा कि इससे भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योगों के लिए जबरदस्त अवसर खुलते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री के 'रक्षा में आत्मनिर्भरता' पर ध्यान केंद्रित करने के साथ भारत के उद्योगों को वैश्विक मांग में बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए और निर्यात तथा नवाचार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा, "हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि निर्णय तेजी से लिए जाएं ताकि हम यहीं भारत में बड़े इंजनों का निर्माण शुरू कर सकें और यह काम भारतीयों के हाथों से शुरू हो।" उन्होंने उन्नत स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र के बढ़ते सामरिक और आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए रक्षा व्यय को महज व्यय के रूप में देखने की धारणा को बदलने का आह्वान किया और कहा कि इसे गुणक प्रभाव वाले आर्थिक निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "हाल तक, रक्षा बजट को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हिस्से के रूप में नहीं देखा जाता था। आज, वे विकास के चालक हैं।" उन्होंने कहा कि भारत, बाकी दुनिया के साथ, पुनः शस्त्रीकरण के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसकी विशेषता रक्षा क्षेत्र में पूंजी निवेश है। उन्होंने विभाग से आग्रह किया कि वे अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के सामाजिक प्रभाव विश्लेषण सहित अपनी योजना और आकलन में रक्षा अर्थशास्त्र को शामिल करें।

रक्षा मंत्री सिंह ने एक लाख करोड़ रुपये की बजट के साथ हाल ही में शुरू की गई अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना का भी उल्लेख किया, जो रक्षा क्षेत्र के नवाचार और उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी की खरीद को प्राथमिकता देता है। उन्होंने रक्षा विभाग को इस तरह की परियोजनाओं (खासकर स्टार्ट-अप, एमएसएमई और निजी क्षेत्र से) के सुचारू कार्यान्वयन और समय पर वित्त पोषण सुनिश्चित करने में सक्रिय सहायक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि पहली बार रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पूंजी के माध्यम से हथियार प्रणालियों के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही उन्होंने विभाग से इस बदलाव से संबंधित वित्तीय गतिविधियों के लिए तैयार रहने का आग्रह भी किया।

राजनाथ सिंह ने विभाग के नए आदर्श वाक्य 'सतर्क, चुस्त, अनुकूल' की प्रशंसा की और कहा कि ये महज शब्द नहीं हैं, बल्कि आज के तेजी से विकसित हो रहे रक्षा माहौल में आवश्यक कार्य संस्कृति का प्रतिबिंब हैं। उन्होंने अधिकारियों से केवल बाहरी ऑडिट या सलाहकारों पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आंतरिक सुधार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "आंतरिक मूल्यांकन के जरिए किए गए सुधार जीवंत संगठन बनाते हैं। ये सुधार अधिक जैविक हैं, जिनमें बाधाएं कम हैं।"

भारतीय हज समिति ने हज 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की

ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई 2025 तक किए जा सकेंगे

जालंधर ब्रीज . अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय हज समिति ने मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण पवित्र तीर्थयात्रा हज 2026 के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक तीर्थयात्री अपने आवेदन आधिकारिक हज पोर्टल https://hajcommittee.gov.in या "हज सुविधा" मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। यह आईओएस और एंड्रॉयड दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन 7 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 (रात 11:59 बजे) तक किए जा सकते हैं।

आवेदकों को अपने फॉर्म जमा करने से पहले दिशा-निर्देश और वचन-पत्र अच्छी तरह से पढ़ने होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि को या उससे पहले जारी किया गया मशीन से पढ़ने योग्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट होना अनिवार्य है, और इसे कम से कम 31 दिसंबर 2026 तक वैध होना चाहिए।

हज कमेटी ने आवेदकों को यह भी सलाह दी है कि वे आवेदन करने से पहले अपनी तैयारियों पर ध्यान पूर्वक विचार करें। मृत्यु या गंभीर चिकित्सा आपातकाल जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों को छोड़कर, रद्दीकरण से वित्तीय नुकसान भी हो सकता है।

यह घोषणा हजारों भारतीय मुसलमानों के लिए भारत सरकार के समर्थन और सुविधा के साथ हज करने की अपनी आध्यात्मिक आकांक्षा को पूरा करने के लिए एक और अवसर की शुरुआत है।

विस्तृत निर्देशों के लिए https://hajcommittee.gov.in पर जाएं।

"Collab Engine" अभियान को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया फ्लैग-ऑफ

जालंधर ब्रीज . *केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री माननीय अजय टम्टा जी ने आज अपने से देशव्यापी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्थायित्व (Sustainability) अभियान "Collab Engine" को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।*

यह अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के Mission LiFE (Lifestyle for Environment) विज़न से प्रेरित है और इसका उद्देश्य देशभर में स्वच्छ और सतत यातायात के प्रति जागरूकता फैलाना है।

***Collab Engine* एक युवा-नेतृत्व वाला ईवी रोड अभियान है, जो :** *- 25+ शहरों को जोड़ते हुए 10,500+ किलोमीटर की दूरी तय करेगा,*

- *विश्व कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास कर रहा है (सबसे लंबी ईवी ड्राइव),*
- *इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्रोत्साहित करेगा।*

अभियान की शुरुआत एक इलेक्ट्रिक वाहन से की गई है, जो इस पूरे मार्ग में प्रदूषण-मुक्त यात्रा करेगा। टीम रास्ते में विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर जनसंवाद और जागरूकता सत्र आयोजित करेगी।

इस अवसर पर टम्टा ने कहा : *"युवाओं की यह पहल आने वाले भारत की हरित और जिम्मेदार भविष्य की ओर एक मजबूत कदम है। सरकार इस तरह के अभियानों का स्वागत करती है और इन्हें अपना समर्थन देती है।"*

Collab Engine की टीम ने बताया कि इस यात्रा के दौरान वे स्थानीय प्रशासन, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और छात्र समुदाय के साथ संवाद करेंगे और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों, हरित ऊर्जा, और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाएंगे।

Collab Engine टीम अब इस प्रेरणास्पद यात्रा के माध्यम से देशभर के नागरिकों को जागरूक करने के लिए निकल चुकी है।

कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र को श्रद्धांजलि

जालंधर ब्रीज . भारतीय सेना ने कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र (मरणोपरांत) को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। 13 जेएके राइफल्स (कारगिल) के वीर योद्धा कैप्टन बत्रा को 7 जुलाई, 1999 को ऑपरेशन विजय के दौरान हुई उनकी अविस्मरणीय शहादत, उनके असाधारण साहस और निस्वार्थ बलिदान के लिए याद किया गया।

सम्मान समारोह की शुरुआत नायब सूबेदार घनश्याम दास द्वारा 13 जेएके राइफल्स के हिस्से के रूप में कैप्टन विक्रम बत्रा की वीरतापूर्ण सेवा के परिचय के साथ हुई। समारोह के दौरान, कैप्टन बत्रा के परिवार के निकटतम परिजन, जिनमें उनके पिता गिरधारी लाल बत्रा और जुड़वां भाई श्री विशाल बत्रा शामिल थे, को भारतीय सेना के अधिकारियों की ओर से स्मृति चिन्ह और आभार पत्र भेंट किया गया। यह कार्यक्रम शहीदों के परिवारों से जुड़ने और उन्हें यह भरोसा दिलाने के लिए एक विशेष आउटरीच अभियान का हिस्सा था कि उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा।

इस अवसर पर, एनसीसी चंडीगढ़ के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर वी एस चौहान ने कैडेटों को संबोधित करते हुए उन्हें कैप्टन बत्रा के साहसी जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। डीएवी कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीमती मोना नारंग ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि कैप्टन विक्रम बत्रा संस्थान के पूर्व छात्र थे, उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी और बलिदान ने कॉलेज को गौरवान्वित किया है।

ब्रिक्स नेताओं का घोषणापत्र

जालंधर ब्रीज . पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता है - पैरा 34

हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। हम आतंकियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्तपोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित सभी तरह (रूपों और अभिव्यक्तियों में) के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

हम आतंकवाद को कतई सहन न करने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंडों को अस्वीकार करने का आग्रह करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संस्थाओं पर ठोस कार्रवाई का आह्वान करते हैं। ब्रिक्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों पर अब तक की सबसे मजबूत भाषा अपनाई (पैरा 6) हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार के लिए समर्थन दोहराते हैं, ताकि इसे और अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधि, प्रभावी और कुशल बनाया जा सके और परिषद की सदस्यता में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके। इससे यह मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का पर्याप्त रूप से जवाब दे सकेगा और ब्रिक्स देशों सहित अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के उभरते और विकासशील देशों की वैध आकांक्षाओं का समर्थन कर सकेगा। हम इस बात पर बल देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार से वैश्विक दक्षिण की आवाज बुलंद होगी। हम संयुक्त राष्ट्र में, सुरक्षा परिषद सहित, अधिक बड़ी भूमिका निभाने के लिए ब्राजील और भारत की आकांक्षाओं के लिए समर्थन दोहराते हैं।

पर्यावरण के रचनात्मक प्रशासन के जरिए सतत् हरित बदलाव

जालंधर ब्रीज . पर्यावरण कुजनेट्स वक्र (एनवायरनमेंट कुजनेट्स कर्व) से हासिल पर्यावरण के प्रशासन से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान यह मानता है कि देश पहले विकास करते हैं और बाद में सफाई में जुटते हैं। यह अनुभवजन्य अंतर्दृष्टि अब विकसित हो चुके उन देशों के अनुभवों से प्रेरित है, जिन्होंने विकास की प्रक्रिया में संसाधन संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु देश और विदेश में प्राकृतिक पर्यावरण का दोहन किया। लेकिन ऐसी सुविधा भारत जैसे देशों को नसीब नहीं है, जिन्हें अपनी विशाल आबादी की विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अभी भी तेज गति से विकास करने की जरूरत है।

जब 2014 में एनडीए सत्ता में आई, तो चुनौती हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मूल सिद्धांतों - "सुधार, प्रदर्शन और बदलाव" - पर आधारित विकास एवं प्रगति को गति देने की थी। इन सिद्धांतों में जरूरत के हिसाब से पर्यावरण की सुरक्षा के सख्त उपायों से समझौता किए बिना 'व्यवसाय करने में आसानी' की सुविधा प्रदान करते हुए तेजी गति से विकास करना शामिल था। आज 2025 में, हम न सिर्फ इस चुनौती से निपट पाने में सफल रहे हैं बल्कि हमने शासन का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसे सारी दुनिया ने माना है। प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ था: इस प्रणाली को एक ऐसी प्रणाली में बदला जाए जो "इकोलॉजी और अर्थव्यवस्था" दोनों के लिए फायदेमंद हो। वर्ष 2014 में 'स्वच्छ भारत मिशन' की शुरुआत हमारी पहली बड़ी पहल थी। यह पहल स्वच्छता से आगे बढ़कर कचरे के प्रबंधन व पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करने तक जा पहुंची। इस मिशन ने पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को सामाजिक विकास के साथ जोड़ने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाया। इस मिशन को सभी नागरिकों को शामिल करते हुए एक जन आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था और एक स्वच्छ एवं संसाधन के मामले में अपेक्षाकृत अधिक कुशल भारत की चाहत को आगे बढ़ाया गया था। विभिन्न शहरों में नागरिकों को पारदर्शी तरीके से वास्तविक समय में वायु की गुणवत्ता की निगरानी से जुड़ी सुविधा प्रदान करने के तुरंत बाद राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ किया गया।

वर्ष 2014 में शुरू की गई 'मेक इन इंडिया' पहल में भी कड़े पर्यावरण अनुपालन मानकों को शामिल किया गया। इससे यह साबित हुआ कि हम इकोलॉजी की स्थिरता को बनाए रखते हुए मैन्यूफैक्चरिंग को अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर और तेज गति से बढ़ावा दे सकते हैं। ऊर्जा संबंधी दक्षता को बढ़ावा देने और ऊर्जा पर आधारित अधिक संख्या में उद्योगों को शामिल करने के उद्देश्य से 2015 में प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना का विस्तार किया गया। इससे ऊर्जा संबंधी दक्षता के लिए एक बाजार-आधारित तंत्र का निर्माण हुआ।

कचरे के कारगर प्रबंधन, संसाधन संबंधी दक्षता में बढ़ोतरी और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2016 से कचरे के प्रबंधन के सभी प्रमुख नियमों को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण का बुनियादी सिद्धांत बाजार आधारित तंत्र और "प्रदूषक द्वारा भुगतान के सिद्धांत" पर आधारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व से जुड़े ढांचे पर निर्भरता में निहित है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, ई-कचरा प्रबंधन नियम तथा टायर, बैटरी एवं प्रयुक्त तेल अपशिष्ट प्रबंधन नियम आदि इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर तैयार किए गए थे। इससे एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण हुआ, जिसके तहत विभिन्न सामग्रियों के लगभग 4,000 पुनर्चक्रणकर्ताओं को पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के रूप में अनौपचारिक क्षेत्र से हटाकर औपचारिक क्षेत्र में लाया गया है। इस कदम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1600 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022 में शुरू किए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पोर्टल चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल 61,055 उत्पादकों ने प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-कचरा, बेकार टायर, बैटरी के कचरे और प्रयुक्त तेल के क्षेत्र में काम करने हेतु ईपीआर पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। अपशिष्ट नियम, 2022 के प्रकाशन और ईपीआर पोर्टल की शुरूआत के बाद, शोधित अपशिष्ट की मात्रा वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन नियमों के प्रकाशन से पहले 3.6 एमएमटी प्रति वर्ष की तुलना में बढ़कर 127.48 एमएमटी प्रति वर्ष हो गई है। यह सभी हितधारकों के सहयोग एवं समर्थन से संभव हुआ है।

भूपेंद्र यादव
(केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं)

प्रक्रियागत देरी में कमी लाने और एक व्यापक पर्यावरणीय मूल्यांकन करने के उद्देश्य से 2018 में 'परिवेश' (प्रो-एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाई इंटरएक्टिव, वर्चुअस एंड एनवायरनमेंटल सिंगल-विंडो हब) नाम के एक ऑनलाइन आईटी टूल का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के 'डिजिटल इंडिया' के विजन को साकार करते हुए, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने व्यवसाय जगत और पर्यावरण नियामकों के बीच के संवाद में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। 'परिवेश' ने पर्यावरण संबंधी मंजूरी की बोझिल एवं कागज-आधारित प्रक्रिया को एक सुव्यवस्थित एवं मजबूत डिजिटल अनुभव में बदल दिया है। इस दृष्टिकोण ने जहां पर्यावरण से जुड़े सख्त मूल्यांकन को बनाए रखा है, वहीं इस प्रक्रिया में लगने वाले समय में काफी कमी ला दी है और पारदर्शिता को बढ़ाया है।

वर्ष 2019 में शहरों पर केन्द्रित कार्य योजनाओं से लैस 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (एनसीएपी) के आधिकारिक शुभारंभ ने हमें नीति निर्माता एवं नियामक से बदलकर अमल करने वाला बना दिया है। एनसीएपी का लक्ष्य 2025-26 तक पीएम10 सांद्रता में 40 प्रतिशत की कमी लाना या आधार वर्ष 2017-18 की तुलना में 60 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर के राष्ट्रीय मानक को हासिल करना है। एनसीएपी के साथ-साथ सीपीसीबी ने एनसीएपी के तहत आने वाले 131 शहरों में वायु की गुणवत्ता के रुझान की बारीकी से निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे वायु की गुणवत्ता निरंतर बेहतर हुई है। वर्ष 2021 में, गैर-प्राप्ति वाले शहरों में वायु गुणवत्ता के नियमन हेतु पोर्टल (पीआरएएनए) को कागज रहित परियोजना प्रबंधन के एकल बिंदु वाले वेब-आधारित उपकरण के रूप में शुरू किया गया। इससे स्वच्छ वायु से जुड़े उपायों के कार्यान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर नजर रखना संभव हो सकेगा।

1 जुलाई, 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाली प्लास्टिक शीट पर प्रतिबंध ने जहां पर्यावरण के क्षेत्र में साहसिक नेतृत्व का परिचय दिया, वहीं उसी वर्ष शुरू किए गए 'जल जीवन मिशन' ने पानी की सुलभता को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ जोड़ा।

एक व्यापक 'भारत शीतलन कार्य योजना' विकसित करके भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। इस कार्य योजना में विभिन्न क्षेत्रों की शीतलन संबंधी जरूरतों को पूरा करने वाले एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण समावेश है तथा इसमें ऐसे कार्यों की सूची दी गई है, जो शीतलन से जुड़ी मांग को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

नगर निगम जालंधर में बी एंड आर शाखा और ओ एंड एम शाखा के तालमेल की कमी से

जनता के पैसे की बर्बादी

वर्कशाप चौक से गाजी गुल्ला की तरफ जाते रोड पर ढक्कन ढूंडने के लिए खोदी नई सड़क।

• **जालंधर ब्रीज .** विशेष रिपोर्टर

नगर निगम जालंधर में बी एंड आर शाखा और ओ एंड एम शाखा के बीच तालमेल की कमी के कारण आम जनता से वसूला गया टैक्स बर्बाद किया जा रहा है। अधिकारी इस पैसे को बिना किसी योजना के पानी की तरह बहा रहे हैं।

शहर के अलग-अलग इलाकों में इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे कि साई दास स्कूल से लेकर प्रकाश आइसक्रीम और श्रीकृष्ण मुरारी मंदिर मार्केट के बाहर बी एंड आर शाखा द्वारा कई जगहों पर जेसीबी मशीन से नई बनी सड़कों को उखाड़ा जा रहा है। शहर में कई जगहों पर जेसीबी मशीन से खुदाई हो रही है, लेकिन खोदाई के वक्त ना तो कोई जूनियर इंजीनियर मौजूद होता है और ना ही कोई कर्मचारी, जिससे यह तय हो सके कि कहां से खोदाई करनी है।

इस लापरवाही का नतीजा यह होता है कि ठेकेदार द्वारा बनाई गई सड़कों के नीचे दबे ढक्कन सही तरीके से नहीं निकाल पाते और बार-बार नई बनी सड़कें खोद दी जाती हैं, जिससे सरकारी पैसों की बर्बादी होती है। इसके साथ ही शहर की नई सड़कों पर जेसीबी से खोदाई पर भी कोई रोक नहीं और अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हैं।

प्रकाश आइसक्रीम के सामने बीच सड़क पर रखी पाइपलाईन दे रही बड़े हादसे को न्यौता।

वार्ड नं. 69 में सीवर और सड़क की खराब स्थिति

बत्रा पैलेस के बाहर लगभग दो महीने से खोदकर छोड़ी हुई सड़क।

इसी तरह वार्ड नंबर 69 में आने वाले मोहल्ला गुरदेव नगर और गाजी गुल्ला में सीवर लाइन टूट जाने के कारण पिछले एक महीने से 69 इंच की पाइपलाइन डालने का काम अधूरा पड़ा है। यहां करीब लगभग दो महीने से सड़क को खोद कर छोड़ा हुआ है ताकि 69 इंच के पानी को 8 इंच की सीवर लाइन से जोड़ा जा सके।

लगातार बारिश के दिनों में इस टूटे रास्ते से स्कूल जाने वाले बच्चे और इलाके के लोग गिर कर घायल हो रहे हैं। सड़क पर पड़ी पाइपें किसी भी वक्त बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं।

जब इस बारे में नगर निगम बी एंड आर शाखा के एसडीओ से बात की गई तो उन्होंने मोहल्ला निवासियों को सिर्फ आश्वासन दिया कि काम पूरा करवा दिया जाएगा। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की नींद तभी खुलेगी जब इस गड्ढे में गिरकर कोई बड़ा हादसा होगा या किसी की जान चली जाएगी।

ऐसे में सवाल यह है कि जनता से वसूला गया टैक्स कब तक इस लापरवाही की भेंट चढ़ता रहेगा? कब तक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी? कब तक नई सड़कों को बिना वजह खोद-खोद कर पैसों की बर्बादी की जाती रहेगी?

आम जनता की मांग है कि बी एंड आर शाखा और ओ एंड एम शाखा में सही तालमेल बने, काम की मॉनिटरिंग की जाए और मौके पर जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहें ताकि जनता को बार-बार परेशानी न हो और टैक्स का सही इस्तेमाल हो सके।

खाली प्लॉटों से कूड़ा न हटाने पर 289 लोगों को नोटिस जारी

सरकारी विभागों द्वारा कूड़ा हटाने पर प्रशासन सफाई खर्च वसूलेगा; राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगी रेड एंट्री

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल द्वारा खाली प्लॉटों से कूड़ा हटाने के दिए गए आदेशों के बाद, जालंधर प्रशासन ने जिले भर के विभिन्न प्लॉट मालिकों को 289 नोटिस जारी किए हैं। डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मानसून सीजन में बीमारियां फैलने की आशंका और जन स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर जिला भर के प्लॉट मालिकों को 10 जुलाई 2025 तक अपने खाली प्लॉटों से कूड़ा-कचरा व अन्य अपशिष्ट पदार्थ हटवाने के निर्देश दिए गए है।

इसके अलावा, प्लॉटों के चारों ओर चारदीवारी या बाड़ लगाने के भी आदेश दिए गए हैं ताकि अवैध रूप से कूड़ा डालने पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर ,नगर निगम जालंधर द्वारा 99, नगर कौंसिल आदमपुर द्वारा 14, नगर पंचायत अलावलपुर द्वारा 4, नगर कौंसिल भोगपुर द्वारा 25, नगर पंचायत बिलगा द्वारा 8, नगर कौंसिल गोराया द्वारा 9, नगर कौंसिल करतारपुर द्वारा 14, नगर पंचायत लोहियां खास द्वारा 29, नगर पंचायत मेहतपुर द्वारा 30, नगर कौंसिल नकोदर द्वारा 9, नगर कौंसिल फिल्लौर द्वारा 16, नगर कौंसिल नूरमहल द्वारा 5 और नगर पंचायत शाहकोट द्वारा 27 नोटिस जारी किए गए हैं। डा. अग्रवाल ने बताया कि जारी किए गए नोटिसों में प्लाट मालिकों को नोटिस जारी होने की तिथि से 2 दिनों के भीतर प्लाटों की सफाई और प्लाट के चारों ओर चारदीवारी करवाने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने बताया कि ऐसा न करने पर सरकारी विभाग सफाई करवाएंगे, जिसका खर्च प्लाट मालिक से जुर्माने के तौर पर वसूला जाएगा। यदि कोई लागत जमा नहीं करता है, तो राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, जुर्माने के अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986, पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने नगर निगम जालंधर के कमिश्नर गौतम जैन और अन्य अधिकारियों के साथ गुरुवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और आदर्श नगर चौक के पास एक खाली प्लॉट से कचरा हटाया। उन्होंने कहा कि जिन प्लॉटों में अधिकारी सफाई करवाएंगे, वहां सफाई का खर्च प्लॉट मालिकों से वसूला जाएगा। डा.अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि यह कदम पूरी तरह से जन स्वास्थ्य के हित में उठाया गया है ताकि जिले के लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके, विशेष कर चल रहे बरसात के मौसम में जब वेक्टर जनित बीमारियाँ तेजी से फैल सकती हैं। उन्होंने स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने और निवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जालंधर प्रशासन की वचनबद्धता दोहराई।

सिर्फ 11 मिनट में सत्र खत्म होने पर विपक्ष ने सरकार को घेरा

बाजवा बोले- यह 'आप' सरकार की धोखेबाजी

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र का पहला दिन केवल 11 मिनट में समाप्त हो गया, जिसके बाद पंजाब

विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब को परेशान करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की घोर निष्ठाहीनता को दृढ़ता से चुनौती दी। उन्होंने कहा, "मैंने विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां से विशेष सत्र के विस्तार का औपचारिक अनुरोध किया, जिसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया- राज्य भर में कानून और व्यवस्था में खतरनाक गिरावट और आप सरकार द्वारा शुरू की गई विवादास्पद भूमि पूलिंग नीति। इन गंभीर चिंताओं को दूर करने के बजाय, आप सरकार ने सत्र के पहले दिन का समापन केवल 11 मिनट में करने का विकल्प चुना। यह स्पष्ट रूप से आप सरकार की धोखेबाजी और विपक्ष द्वारा पूछे गए वैध सवालों से बचने की उसकी कोशिश को दर्शाता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि वे सत्र के दूसरे दिन चर्चा के लिए कैसे संपर्क करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाजवा ने कहा कि आप सरकार का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का प्राथमिक मकसद विधानसभा में बेअदबी विरोधी विधेयक पेश करना है। उन्होंने कहा कि अब तक वे विपक्ष को बिल की एक प्रति प्रदान करने में विफल रहे हैं, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

झींजर बोले- यह पंजाब के साथ महंगा मज़ाक

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

युवा अकाली दल के अध्यक्ष व शिरोमणि अकाली दल की कार्यकारिणी

के सदस्य सरबजीत सिंह झींजर ने आज आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा बुलाए गए दो दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र पर गंभीर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी ने दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया और उसका पहला दिन महज़ 11 मिनट में समाप्त कर दिया गया, जिसमें केवल शोक प्रस्ताव ही पढ़े गए। सरबजीत सिंह झींजर ने कहा, "जब पंजाब को जरूरी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के लिए एक लंबा सत्र चाहिए था—जैसे कि बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसानों की ज़मीन को लूटने वाली लैंड पूलिंग पॉलिसी, खराब होती स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य कई समस्याएं — तब भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार इस तरह से जवाबदेही से भाग रही है। पहले दिन की कार्यवाही सिर्फ 11 मिनट में खत्म कर 2 करोड़ रुपये की जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर दिया गया। यह पूरी तरह अस्वीकार्य है।" झींजर ने यह भी सवाल उठाया कि शोक प्रस्ताव के बाद कोई कार्य क्यों नहीं हुआ। "अगर सरकार कल पवित्र ग्रंथों की बेअदबी से जुड़े बिल को लाने जा रही है, तो आज ज़ीरो ऑवर क्यों नहीं रखा गया?

390 सरकारी इमारतों पर लगेंगे 30 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा प्लांट

150 करोड़ रुपए की लागत वाला प्रोजैक्ट मार्च 2026 तक चालू किया जायेगा: अमन अरोड़ा

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने आज बताया कि राज्य की प्राकृतिक ऊर्जा सम्बन्धी क्षमता में विस्तार करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार द्वारा मार्च 2026 तक राज्य भर में 390 सरकारी इमारतों की छतों पर 30 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किये जाएंगे। अमन अरोड़ा पंजाब ऊर्जा विकास अथॉरिटी (पेडा) द्वारा चलाए जा रहे चल रहे प्रोजेक्टों का जायज़ा ले रहे थे। इस मौके पर उनके साथ पेडा के चेयरपर्सन डा. सुखचैन गोगी और प्रमुख सचिव नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत श्री अजोए कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। इस प्रोजेक्ट संबंधी जानकारी देते हुए अमन अरोड़ा ने बताया कि 150 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से विभिन्न सरकारी विभागों के बिजली ख़र्च में वार्षिक 15 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्धी टैंडर प्रक्रिया मुकम्मल हो चुकी है, जिससे इस प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।

बता दें कि इस प्रोजेक्ट के अधीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण, परिवहन, कृषि और किसान कल्याण, पर्यटन और सांस्कृतिक मामले, गृह मामले और न्याय, मैडीकल शिक्षा और अनुसंधान, स्थानीय निकाय और जल स्रोत विभाग सहित 25 प्रमुख विभागों की इमारतों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब ने पिछले तीन सालों में नवीकरणीय ऊर्जा में प्रभावशाली प्रगति दर्ज की है जिसके अंतर्गत 1098 सरकारी इमारतों की छतों पर 7.7 मेगावाट सामूहिक क्षमता वाले सौर ऊर्जा प्लांट लगाए गए हैं, जो स्थायी ऊर्जा के प्रति राज्य सरकार की वचनबद्धता को दर्शाते हैं।

ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 3 पंचायत सचिव निलंबित

जालंधर (जालंधर ब्रीज). जालंधर ज़िले के तीन पंचायत सचिवों को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से उनके पदों से निलंबित कर दिया गया है। यह निलंबन डिप्टी कमिश्नर डा.हिमांशु अग्रवाल द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से प्राप्त आदेशों के अनुसार, पंचायत सचिव प्रशोतम लाल और दिलबाग सहोता (पंचायत समिति जालंधर पश्चिम) तथा पंचायत सचिव परविंदर सिंह, पंचायत समिति फिल्लौर को उनके पदों से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय ज़िला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जालंधर रहेगा। स्वच्छ एवं जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने की पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, डा.अग्रवाल ने कहा कि ज़िले के लोगों को अच्छा और पारदर्शी प्रशासन प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वालों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

महिला सशक्तिकरण के लिए की नई पहल

लड़कियों की आत्म-रक्षा प्रशिक्षण और कोचिंग कक्षाएं शुरू करने के निर्देश

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई पहल करते हुए, जिला प्रशासन ने जालंधर में लड़कियों के लिए आत्म-रक्षा के नए बैच और निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं शुरू करने की योजना तैयार की है। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, डिप्टी कमिश्नर डा.हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि अन्य पहलों के अलावा, जालंधर प्रशासन लड़कियों के लिए आत्म-रक्षा प्रशिक्षण और कोचिंग कक्षाओं के नए बैच शुरू करेगा।

डा.अग्रवाल ने लड़कियों में आत्म-रक्षा एंव आत्म-विश्वास के महत्व पर ज़ोर दिया, जिसके तहत जिला प्रशासन द्वारा यह प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान, आत्म-रक्षा के लिए आवश्यक तकनीकें सिखाई जाएंगी, जिससे छात्राएं सुरक्षित रह सकेंगी और किसी भी स्थिति में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकेंगी। डिप्टी कमिश्नर ने 12वीं कक्षा के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लड़कियों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं शुरू करने को भी कहा। डा. हिमांशु अग्रवाल ने लड़कियों के कल्याण और विकास के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इससे पहले प्रशासन ने शाहकोट ब्लॉक के 30 गाँवों में एनीमिया की रोकथाम के लिए लड़कियों में हीमोग्लोबिन की जाँच के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। लड़कियों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधाएँ प्रदान करने की पंजाब सरकार की वचनबद्धता दोहराते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि लड़कियों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

युद्ध नशियां विरुद्ध का 31वां दिन

पंजाब पुलिस द्वारा 129 नशा तस्कर गिरफ़्तार; 4.2 किलो हेरोइन बरामद

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

'युद्ध नशों विरुद्ध' के 131वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 129 नशा तस्करों को गिरफ़्तार करके उनके कब्ज़े में से 4.2 किलो हेरोइन, 509 ग्राम अफ़ीम और 23,370 रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। इससे सिर्फ़ 131 दिनों के अंदर गिरफ़्तार किये गए कुल नशा तस्करों की संख्या 21,356 हो गई है। यह आपरेशन डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव के आदेशों पर राज्य के सभी 28 जिलों में एक ही समय चलाया गया।

आपरेशन के विवरण देते हुये स्पैशल डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 84 गज़टिड अधिकारियों की निगरानी अधीन 1300 से अधिक पुलिस कर्मचारियों के सम्मिलन वाली 180 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 414 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके चलते राज्य भर में 92 ऐफआईआरज़ दर्ज की गई। उन्होंने आगे कहा कि दिन भर चले इस आपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 456 शक्की व्यक्तियों की जांच भी की। स्पैशल डीजीपी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य में से नशों के ख़ात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति-इनफोरसमैंट, डी-एडिकशन और प्रीवैंशन (ईडीपी) - लागू की गई है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के तौर पर 86 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राज़ी किया है।

मुफ्त राशन लेने वाले लाभार्थी 14 से पहले करवाएं ई-केवाईसी

कपूरथला (जालंधर ब्रीज). जिला खाद्य एवं सप्लाई कंट्रोलर मिस संयोगता की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत मुफ्त राशन का लाभ ले रहे सभी लाभार्थियों से 14 जुलाई 2025 से पहले अपनी ई-केवाईसी करवाने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ई-केवाईसी कराना 14 जुलाई 2025 तक अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई लाभार्थी इस तिथि तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाता, तो उसका राशन कार्ड अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा।

सहकारिता संबंधी साक्षरता कैंप लगाया

कपूरथला (जालंधर ब्रीज). नाबार्ड के जिला विकास मैनेजर जस्मिंदर सिंह बिंद्रा के नेतृत्व में कालासंघिया में कपूरथला सेंट्रल सहकारी बैंक के सहयोग से सहकारिता संबंधी साक्षरता कैंप लगाया गया। कैंप का उद्देश्य किसानों को सहकारी आंदोलन से जोड़कर उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना था, जिसके तहत उन्हें नाबार्ड और सहकारी बैंकों द्वारा किसानों की सहायता के लिए लागू की गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर नाबार्ड के मैनेजर बिंद्रा ने बताया कि नाबार्ड द्वारा बैंकों को बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि बैंकों के माध्यम से इसका उपयोग किसानों की भलाई के लिए किया जा सके। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे भी लगाए गए। समारोह के दौरान कमलजीत सिंह, मनोज सांगर और परमजीत सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

सचिन तेंदुलकर को लॉर्ड्स में मिले एक साथ दो सम्मान

स्पोर्ट्स डेस्क. क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच से पहले लॉर्ड्स में सम्मानित किया गया। तेंदुलकर ने लॉर्ड्स म्यूजियम में लगी अपनी तस्वीर का अनावरण किया। इसके बाद लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में लगे बेल को बजाकर मैच का आगाज करने के संकेत दिए। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैच की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच क्रिकेट के मक्का यानी लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए उनका सम्मानित किया गया। लॉर्ड्स के म्यूजियम में सचिन की एक पुरानी तस्वीर

फोटो-बीसीसीआई

लगाई गई है।

मैच से पहले ही सचिन तेंदुलकर से ही इस तस्वीर का अनावरण कराया गया। तस्वीर यंग सचिन की है। इसमें वह भारत की पुरानी जर्सी में नजर आ रहे हैं। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और एमसीसी ने भारतीय दिग्गज को उनके योगदान के लिए ये सम्मान दिया। सचिन ने लॉर्ड्स के मैदान पर 5 टेस्ट मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने केवल 195 रन बनाए, जिसमें सर्वोच्च स्कोर 37 रन का रहा है।

आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों की फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

स्कूल शिक्षा विभाग और सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधियों को दिया प्रशिक्षण

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी व निजी स्कूलों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड करने के उद्देश्य से, सहायक कमिश्नर फूड डा. हरजोतपाल सिंह और फूड सेफ्टी अधिकारी राशू महाजन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग और सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधियों के लिए एक प्रशिक्षण सेशन आयोजित किया। कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब दिलराज सिंह के निर्देश पर आयोजित इस प्रशिक्षण सेशन के दौरान, खाद्य विंग के अधिकारियों ने बताया कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी व निजी स्कूलों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

उन्होंने दोनों विभागों के अधिकारियों से आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों को इस संबंध में जागरूक करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्र और मिड डे मील सभी लाभार्थियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाए। इस दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at DB Corp Ltd, Near Subhanpur Bus Stand,Hamira, Kapurthala-144802(Punjab) and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.